आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बुधवार 28.05.2025
समय 1830

मुख्य समाचार :–

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चौदह खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 11 प्रस्ताव स्वीकृत।
- छठे राज्य वित्त आयोग ने नई टिहरी में स्थानीय निकायों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की।
- उत्तराखंड में इस साल मानसून के समय से पहले आने की संभावना।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने चौदह खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य– एम.एस.पी. में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि सरकार ने विपणन सत्र 2025–26 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है, ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रामतिल के लिए आठ सौ बीस रुपये प्रति क्विंटल, रागी के लिए पांच सौ छियानबे रुपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए पांच सौ नवासी रुपये प्रति क्विंटल और तिल के लिए पांच सौ उनासी रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की गई है।

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025–26 के लिए संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत ब्याज छूट को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

राज्य मंत्रिमंडल बैठक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड की पहली योग नीति और कर्मचारियों, पेंशनरों व उनके आश्रितों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज के लिए नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने पत्रकारों को बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 में संशोधन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। स्थानीय लोगों के रोजगार पर ध्यान देते हुए नियमावली में प्रावधान किए गए। विभिन्न विभागों में पांच करोड़ तक के काम स्थानीय के माध्यम से किये जाते थे। ये सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है। उन्होंने बताया कि अटल आयुष्मान योजना और राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए सरकार द्वारा 75 करोड़ का ऋण दिया जाएगा, ताकि अस्पतालों की प्रतिपूर्ति की जा सके।

श्री बगोली ने बताया कि देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों के लिए एम्स ऋषिकेश की तरह किसी सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से उनके रहने और खाने की व्यवस्था सस्ती दरों पर की जाएगी। इसके लिए जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने बताया कि बैठक में उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल की नई नीति मंजूर की गई है। इसमें उद्योगों को चार श्रेणी में बांटा गया है। यह आगामी पांच साल के लिए होगी।

राज्य वित्त आयोग

छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. रविशंकर और सदस्य पी.एस जंगपांगी ने आज नई टिहरी में स्थानीय निकायों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयोग के दायित्वों, नगर निकायों और पंचायतों के अधिकार और इसमें में आ रही समस्याओं पर चर्चा कर उसके समाधान के बारे में सुझाव मांगे गए। आयोग के अध्यक्ष ने नगर निकायों के अध्यक्ष और सभासदों से कहा कि पांच वर्ष की अवधि में बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके लिए सभी को अपने–अपने क्षेत्र में भविष्य के 20 वर्षों की अवधि को योजना सोच–समझकर बनानी होगी। आयोग के सदस्य पी.एस. जंगपांगी ने कहा कि गांवों से शहरों और नगरों की ओर हो रहे सतत् पलायन को देखते हुए इन्हें विकसित किया जाना आवश्यक है।

मानसून

उत्तराखंड में इस साल मानसून के समय से पहले आने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि केरल में मानसून आ गया है और महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अगर मानसून की यही रफ्तार रही, तो उत्तराखंड में 10 से 15 दिनों के भीतर मानसून आ सकता है।

समर कैम्प चम्पावत

शिक्षा मंत्रालय की पहल पर समग्र शिक्षा और एससीईआरटी उत्तराखंड के निर्देशन में चंपावत जिले के सभी विकासखंडों में भारतीय भाषा उत्सव समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों का उद्देश्य बच्चों को भारतीय भाषाओं से परिचित कराते हुए उनके व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और सांस्कृतिक समझ को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. एल. एस. यादव और डॉ. अवनीश शर्मा के अनुसार अब तक कुल 621 बच्चों ने इन गतिविधियों में पंजीकरण कराया है। कैंप में उर्दू, गढ़वाली, संस्कृत, पंजाबी और गुजराती भाषाओं में भाषा कौशल के साथ ही रचनात्मक गतिविधियाँ, नवाचार आधारित कार्यक्रम और सांस्कृतिक संवाद आयोजित किए जा रहे हैं। यह न केवल भाषाई विविधता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति से बच्चों को जोड़ भी रहा है। भाषा विशेषज्ञों द्वारा बच्चों को रोचक जानकारियाँ दी जा रही हैं, जिससे बच्चों की सीखने की रुचि और आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है।

उपाध्यक्ष निरीक्षण

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ऐश्वर्या रावत ने आज रुद्रप्रयाग–गौरीकुंड राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने व्यापारियों और महिला समूहों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं। साथ ही बाबा केदार के दर्शनों पर आये श्रद्धालुओं से यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में उनके अनुभव जाने। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस और विभागों द्वारा अच्छे इंतजाम किये गये हैं। उन्होंने अगस्त्युनि से कुंड, गुप्तकाशी होते हुए फाटा, सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने की बात कही।